एक नजर

नैनीताल के जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी का आकस्मिक निधन

स्वतंत्र चेतना

हल्द्वानी। नैनीताल जिले के जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी का आकस्मिक निधन हो गया। बताया गया है कि हृदयाघात के चलते उनका निधन हुआ। उनके निधन की खबर से सूचना विभाग के साथ ही पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। गिरिजा शंकर जोशी नैनीताल जिले में जिला सूचना अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। सरल, सहज और मिलनसार स्वभाव के कारण वह विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही पत्रकारों के बीच भी लोकप्रिय थे। उनके अचानक निधन की खबर से सूचना विभाग और मीडिया जगत से जुड़े लोग स्तब्ध हैं।निधन की सूचना मिलते ही सांसद अजय भट्ट समेत अधिकारियों और पत्रकारों ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और पत्रकारों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति व शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी के आकस्मिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने भी गिरिजा शंकर जोशी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

पर्वतीय जिलों में 4202 वाहन क्षमता की पार्किंग विकसित

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। आवास विभाग ने पिछले चार वर्षों में 63 पार्किंग परियोजनाओं का कार्य पूरा कर 10 पर्वतीय जिलों में कुल 4202 वाहनों की क्षमता विकसित की है। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और तीर्थस्थलों पर यातायात दबाव कम करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पार्किंग नेटवर्क के विस्तार के तहत प्रमुख शहरों, तीर्थस्थलों और पर्यटन केंद्रों में स्थान की उपलब्धता के अनुसार सतही, बहुमंजिला और स्वचालित पार्किंग का निर्माण किया गया है। विभाग के अनुसार अल्मोड़ा में 1087, नैनीताल में 679, चंपावत में 600, उत्तरकाशी में 477, पिथौरागढ़ में 309, रुद्रप्रयाग में 304, पौड़ी में 256, चमोली में 201, टिहरी में 163 और बागेश्वर में 126 वाहनों की क्षमता विकसित की गई है। सरकार के अनुसार नैनीताल में पार्किंग की समस्या को देखते हुए मेट्रोपोल होटल परिसर क्षेत्र में नई पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूरा होने पर करीब 700 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसी तरह नैनीताल जिले के प्रसिद्ध कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक समय में 500 से अधिक वाहन खड़े किए जा सकेंगे। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निदेर्शों के क्रम में प्रदेश में पार्किंग सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है। 63 परियोजनाओं का कार्य पूरा होने से पर्वतीय जिलों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हुई है और इससे पर्यटकों, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं का प्रमुख गंतव्य बन रहा है। पिछले वर्ष छह करोड़ से अधिक लोग प्रदेश पहुंचे। इसे देखते हुए सरकार यात्री सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम कर रही है। प्रमुख पर्यटन स्थलों और चारधाम यात्रा मार्गों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए पार्किंग सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को अपने सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने पर्यटन, लोक निर्माण, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लघु सिंचाई, एवं ग्रामीण निर्माण के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, गैस वितरण केन्द्रों, राशन की दुकानों, प्रमुख धार्मिक स्थलों और गंगा तटों पर जनभागीदारी से दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम के फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किये जायें। कैबिनेट मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएम मोदी की जनसेवा की यात्रा और सेवा-विकास के कामों को जन-जन तक पहुँचाने और युवाओं को सेवा कार्यों में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं के लाभ और उसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, गरीब कल्याण के कार्य, ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु, प्रदर्शनियां, सेमिनार आदि आयोजित करने के साथ-साथ संस्कृति विभाग में पंजीकृत दलों के माध्यम से पंचायत स्तर पर मंचन तथा सहभागिता करें।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सिर्फ जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा और विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनमानस तक पहुँचाने का एक वृहद अभियान है। इसलिए प्रत्येक जिले में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जाएं। ग्राम प्रधान, सदस्य, ब्लाक प्रमुख, नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला पंचायत प्रतिनिधियों, सांसद एवं विधायक गणों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। बैठक में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह भण्डारी, अपर निदेशक पूनम चंद, सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडे, लघु सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता बी.के. तिवारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मुकेश सिंह परमार, ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विभू रावत और संस्कृति विभाग के अपर निर्देशक शेखर पटवा आदि मौजूद थे।

दून पुस्तकालय में 23 अक्टूबर से सजेगा 16वां 'देहरादून किताब कौतिक'

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। पहाड़ की संस्कृति, साहित्य और युवाओं में पढ़ने-लिखने की आदत को बढ़ावा देने वाली संस्था क्रिएटिव उत्तराखंड की ओर से 23 से 25 अक्टूबर तक दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में 16 वें देहरादून किताब कौतिक का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष आयोजन का संदेश ह्यआओ, दोस्ती करें किताबों सेह्ल रखा गया है।

आयोजन संयोजक हेम पंत ने बताया कि किताब कौतिक में करीब 75 प्रकाशकों की 80 हजार पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। तीन दिवसीय आयोजन में साहित्यिक परिचर्चा, लेखकों से संवाद, करियर काउंसलिंग, बाल लेखन कार्यशाला, विज्ञान एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यक्रम, नेचर वॉक, साहसिक गतिविधियां और सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि क्रिएटिव उत्तराखंड की ओर से अब तक उत्तराखंड के विभिन्न शहरों और कस्बों में 15 किताब कौतिक आयोजित किए जा चुके हैं। देहरादून में होने वाला यह 16वां आयोजन दून पुस्तकालय के हॉल, ओपन थिएटर और गलियारों में आयोजित होगा। पंत ने कहा कि किताब कौतिक का उद्देश्य केवल देहरादून में 80 हजार पुस्तकें लाना नहीं, बल्कि युवाओं में जिज्ञासा, रचनात्मकता और पढ़ने की आदत विकसित करना है। आयोजन में देशभर से साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी शामिल होंगे। आयोजन से पहले देहरादून के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के लिए पांच दिवसीय ह्यबालप्रहरी बाल लेखन कार्यशालाह्ल आयोजित की जाएगी। इसमें बच्चे स्वयं हस्तलिखित पुस्तकें तैयार करेंगे और किताब कौतिक में उनका स्टॉल भी लगाएंगे। इसके अलावा पपेट निर्माण, भाषा-संस्कृति और वॉल पेंटिंग कार्यशालाएं तथा स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। आयोजन की तैयारियों को लेकर शनिवार को दून पुस्तकालय के एम्फीथिएटर में परिचर्चा बैठक हुई। इसमें आयोजन समिति का गठन किया गया।

कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ किया प्रदर्शन, नितिन नवीन का पुतला फूंका

स्वतंत्र चेतना

पौड़ी गढ़वाल। हल्द्वानी दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस कार्यकताओं में आक्रोश है। शनिवार को कांग्रेस कार्यकताओं ने पौड़ी में प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नितिन नवीन का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकताओं ने भाजपा नेतृत्व से सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक भाषा की मयार्दा बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस कार्यकताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक या अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं को सार्वजनिक जीवन में अपने बयानों की मयार्दा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की गरिमा बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस कार्यकताओं ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक हमला मुद्दों और नीतियों के आधार पर होना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी के जरिए नहीं। पौड़ी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी को कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से नितिन नवीन के बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

हरीश रावत ने कांग्रेस के दो पदों से हटने की घोषणा की

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने पूर्व ओएसडी के खिलाफ कथित नकदी और आभूषण बरामदगी से जुड़ी खबरों के बीच उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य और कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य पद से हटने की घोषणा की है।

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में कहा कि टीवी पर देहरादून में उनके पीए के पास भारी मात्रा में नकदी और आभूषण बरामद होने की खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मामले के वास्तविक तथ्यों का खुलासा आने वाले समय में होगा। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति जीना उनके ओएसडी रहे हैं और उन्होंने उनके विभिन्न पदों पर रहते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने कहा कि जीना उनके अनुसार सज्जन, विनम्र और काम करने वाले व्यक्ति रहे हैं। हालांकि, यदि ग्राम सेवकों की भर्ती में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ अथवा इस तरह की कोई गलती किए जाने के प्रमाण सामने आते हैं तो वह ऐसे कृत्य के लिए लज्जित होंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इस आरोप पर विश्वास नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के आगामी चुनाव में काफी कुछ दांव पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे समय में उनके किसी कृत्य से पार्टी के संघर्ष को कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। रावत ने कहा कि वह किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, इसलिए उससे त्यागपत्र देने का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा, ह्यमैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य हूं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य हूं।ह्लउन्होंने कहा कि पार्टी के संघर्ष में उनकी वजह से कोई कमजोरी न आए, इसलिए वह इन दोनों पदों से हटना चाहते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े विवाद का उल्लेख करते हुए हरीश रावत ने कहा कि आयोग का गठन राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में लोक सेवा आयोग को समय पर परीक्षाएं कराने के लिए बाध्य किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती बोर्डों का गठन किया गया।० उन्होंने दावा किया कि उनके करीब तीन वर्ष के कार्यकाल में 42 हजार से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां हुईं। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी और शिकायत मिलने के बाद उन्होंने संबंधित व्यक्ति को पद से हटाया अथवा उनसे इस्तीफा मांगा था। हरीश रावत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में किस तरह का आचरण किया जाएगा, इसका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि नियुक्तियों अथवा परीक्षाओं की प्रक्रिया के दौरान उनसे कोई ह्लएरर ऑफ जजमेंटह्ल हुआ है तो वह उत्तराखंड के लोगों से इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में गड़बड़ी राज्य की आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि उनसे जाने-अनजाने में ऐसा कोई कृत्य हुआ है, जिससे राज्य के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वह स्वयं को इसके लिए दंड का पात्र मानते हैं। रावत ने सार्वजनिक अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास नियुक्तियों के मामलों में उनकी संलिप्तता या हस्तक्षेप के कोई प्रमाण हैं तो उन्हें सीबीआई, ईडी अथवा राज्य पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनसे कोई चूक हुई है तो कानून के अनुसार उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का भी उल्लेख किया और कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में उन्हें खंडूरी से सलाह मिली थी। रावत ने कहा कि उन्होंने संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति उनके पूर्व सेवा रिकॉर्ड के आधार पर की थी। हरीश रावत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रलोभनों से बचना चाहिए और नियुक्तियों एवं परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

कांग्रेस ने आरोप पत्र प्रथम में मुख्यमंत्री पर लगाए सरकारी भूमि घोटाले के आरोप

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। कांग्रेस ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि के निस्तारण और निवेश के नाम पर निजी संस्थाओं को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इसकी विस्तृत जांच की मांग की है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

कहा कि धामी जमीन की खरीद-फरोख्त कर राज्य को गंभीर संकट की ओर धकेले रहे हैं। सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द कर औने पौने दामों में बेचा जा रहा हैं। आज राजपुर रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश में चल रहे भूमि घोटाले में सरकार की संलिप्ता को सामने रखा।कांग्रेस ने आरोप पत्र प्रथम तैयार किया है और इस पहले आरोप पत्र में धामी सरकार पर भू घोटाले की आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी की चार सदस्यीय समिति ने विभिन्न मामलों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की है और आगे कई मामलों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखा जाएगा। माहरा ने यूआईआईडीबी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकारी भूमि के बड़े पैमाने पर निस्तारण की प्रक्रिया में बोर्ड को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 12.50 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि किसी संस्था को दिए जाने अथवा उसकी बोली लगाए जाने की स्थिति में सामान्य तौर पर मामला मंत्रिमंडल के समक्ष जाना चाहिए, लेकिन यूआईआईडीबी को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने प्रस्तावित भूमि नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई मामलों में 90 वर्ष की लीज का प्रावधान है। उनके अनुसार, लीजधारक को बाद में भूमि फ्रीहोल्ड कराने का विकल्प मिलने की स्थिति में सरकारी संपत्ति के दीर्घकालिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंनेने भुगतान की शर्तों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने दावा किया कि सफल बोलीदाता को शुरूआती तौर पर 25 प्रतिशत राशि जमा करनी है, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि अगले दस वर्षों में जमा करने की सुविधा है। माहरा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था से बड़े निवेशकों को सरकारी भूमि का इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ कमाने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने भूमि आवंटन की पात्रता शर्तों को भी स्थानीय उद्यमियों के प्रतिकूल बताया। माहरा के अनुसार, प्रस्तावित प्रक्रिया में करीब 60 करोड़ रुपये की नेटवर्थ, पिछले तीन वर्षों में कम से कम 500 करोड़ रुपये का कारोबार, 25 से अधिक देशों में उपस्थिति और होटल परियोजनाओं के लिए एक हजार कमरों के संचालन का अनुभव जैसी शर्तें रखी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्थानीय छोटे उद्यमियों के बजाय बड़े और बाहरी कारोबारी समूहों को लाभ पहुंच सकता है।

माहरा ने सहसपुर में औद्योगिक भूमि के आवंटन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब 325 बीघा भूमि स्थानीय उद्यमियों को उपलब्ध कराने के बजाय एक शिक्षण संस्थान को दी गई।

उन्होंने भूमि के बाजार मूल्य और आवंटन दर में अंतर का दावा करते हुए सरकार को संभावित राजस्व नुकसान की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि का निस्तारण पारदर्शी नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए, ताकि अधिक राजस्व के साथ स्थानीय निवेशकों को भी अवसर मिल सके। उन्होंने हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में करीब 23,137 वर्गमीटर भूमि से जुड़े मामले पर भी सवाल उठाए। माहरा ने कहा कि कांग्रेस की चार सदस्यीय समिति दस्तावेजों और मामलों की पड़ताल कर रही है तथा सरकारी भूमि से जुड़े मामलों का विस्तृत ब्योरा आगे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने नियमों के उल्लंघन अथवा अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक मनोज रावत, प्रेम बहुखंडी, डॉ प्रतिमा, राजेंद्र, अमर जीत आदि मौजूद रहे।

ईडी कार्रवाई पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस अपने शासन का हिसाब दे : उनियाल

कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल राजनीतिक लाभ की मंशा : चमोली

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भर्ती अनियमितताओं और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुई कथित अनियमितताओं की जवाबदेही देनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश प्रवक्ता एवं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने अलग-अलग बयानों में कांग्रेस पर निशाना साधा।

मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्ष 2016 में भर्ती समेत विभिन्न मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। उन्होंने कहा कि उस दौर से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस को इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने के बजाय अपने शासनकाल की कार्यशैली पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने सिडकुल, यूबीटीईआर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, दरोगा और पटवारी भर्ती समेत विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भर्ती में अनियमितता का सीधा असर मेहनत और प्रतिभा के आधार पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चमोली ने कहा कि ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाने से जांच का औचित्य खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जांच आगे बढ़ने पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और भर्ती अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई चुनावी समय देखकर नहीं रोकी जानी चाहिए। चमोली ने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल में नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अनियमितता में शामिल व्यक्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से इस्तीफे की पेशकश को भी राजनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय भर्ती मामलों में कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

अविरल-निर्मल गंगा के लिए जनभागीदारी जरूरी : डॉ. शैलेन्द्र

जलस्रोत बचेंगे, तभी नदियां और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे : राम सिंह कैड़ा, छोटी धाराओं और जलस्रोतों के संरक्षण पर जोर : रामाशीष

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र ने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अविरल-निर्मल गंगा के लिए सरकार के साथ-साथ समाज, स्वयंसेवी संस्थाओं और धार्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। यदि जल उपलब्ध नहीं रहेगा तो जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल प्रहरी की भूमिका निभानी होगी।

शनिवार को आईएमए ब्लड बैंक के सभागार में गंगा समग्र देहरादून की ओर से आयोजित जल संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए डॉ. शैलेन्द्र ने यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देहरादून में पिछले वर्ष आयी आपदा ने प्राकृतिक जलधाराओं के क्षेत्रों में हुए निर्माण की गंभीरता को सामने रखा। कई स्थानों पर नदी के प्रवाह क्षेत्र तक होटल, मकान और अन्य निर्माण हो गए हैं। प्राकृतिक धाराओं को बाधित कर उन्हें नाले और नालियों में बदलने की प्रवृत्ति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और वर्षाजल संचयन की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वर्षाजल को जमीन में पहुंचाने की व्यवस्था के सकारात्मक

परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि पीने योग्य पानी का इस्तेमाल मुख्य रूप से पेयजल के लिए हो, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले पानी का उपयोग स्नान, कपड़े धोने, सफाई और सिंचाई जैसे कार्यों में किया जा सकता है। डॉ. शैलेन्द्र ने प्लास्टिक प्रदूषण को भी बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि तीर्थस्थलों और धार्मिक यात्राओं में प्लास्टिक बोतलों और अन्य कचरे की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है। केवल सफाई अभियान चलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रदूषणकारी वस्तुओं को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने से रोकना होगा। उन्होंने संतों, धमार्चार्यों और धार्मिक संस्थाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि जल संरक्षण की शुरूआत घर और गांव से होनी चाहिए। जलस्रोतों की सुरक्षा, नदियों की स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। नदी किनारे सफाई के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कूड़ा, गंदा पानी और प्लास्टिक नदियों तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्षाजल संरक्षण, छोटे जलस्रोतों, नालों और जलागम क्षेत्रों को बचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जलस्रोत बचेंगे, तभी नदियां और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने रिस्पना, बिंदाल और सुसवा समेत अन्य जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कैड़ा ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई नौले और झरने सूखने के कगार पर हैं। प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण के लिए पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने कहा कि गंगा संरक्षण केवल पर्यावरण या जल संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा प्रश्न है। बड़ी नदियां छोटी-छोटी धाराओं और सहायक नदियों से मिलकर बनती हैं, इसलिए गंगा को बचाने के लिए पूरे जलतंत्र का संरक्षण जरूरी है। गंगा को केवल हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज या वाराणसी तक सीमित दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्लेशियरों में बदलाव, वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन और भूजल के अत्यधिक दोहन से प्राकृतिक जलचक्र प्रभावित हो रहा है। ऐसे में छोटी धाराओं, जलस्रोतों और नदी के जलग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने नियोजित विकास और विकृत श्रद्धा को भी नदी संरक्षण के सामने चुनौती बताते हुए धार्मिक आस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की जरूरत बताई।

रामाशीष ने कहा कि सरकार की ओर से गंगा की स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को स्थायी सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी सक्रिय भागीदारी करे। नदी किनारे अतिक्रमण रोकने, हरित क्षेत्र विकसित करने, प्लास्टिक के उचित निस्तारण तथा सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में जाने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.डी. चौधरी ने कहा कि मैदान हो या पहाड़, हर जगह मिलकर प्रकृति का संरक्षण करना होगा।

GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar, Apni Pehchan

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिटः साई कृपा, पहली मंजिल, 59/3, राजपुरा रोड, देहरादून, उत्तराखंड248001

ई-नीलामी बिक्री सूचना
सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले/गारंटर को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां 'ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' (जिसे एक्ट के अनुसार 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई थीं। एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस के बाद, एक्ट की धारा 13(12) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी ने इन संपत्तियों का कब्ज